एक नजर में

शहर के अवैध कब्जों पर अब चलेगा बुलडोजर

ग्वालियर. लगातार बारिश और शहर की समस्याओं से जूझ रहे ग्वालियरवासियों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है. इस वर्ष संपत्ति कर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी. नगर निगम परिषद की बैठक में सत्तारूढ़ कांग्रेस की एमआईसी टीम द्वारा कर न बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे भाजपा सहित सभी पार्षदों ने समर्थन दिया. शहर में वर्तमान में करीब 3.25 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जिनसे निगम को सालाना 300 करोड़ रुपये से अधिक की आय होती है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम की जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा है. जैसे सरकारी स्कूल, सामुदायिक भवन, स्टैंड, रैन बसेरे आदि–उन्हें खाली कराया जाएगा.

डेंगू का डंक : 13 वर्षीय बालक संक्रमित

ग्वालियर. ग्वालियर में डेंगू एक बार फिर सिर उठाने लगा है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को एक 13 वर्षीय बालक डेंगू पॉजिटिव पाया गया है, जिसे जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस नए मामले के साथ ही जिले में इस सीजन में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है. मानसून सीजन के दौरान चंबल अंचल में डेंगू और मलेरिया हर साल स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चुनौती बनते हैं. इस बार भी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है. ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष डेंगू के मामले पिछले साल की तुलना में कम हैं.

खाद के टोकन को लेकर किसानों में मारपीट

शिवपुरी. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी के पास स्थित एमपी एग्रो के खाद वितरण केंद्र पर बुधवार को उस समय हंगामा हो गया, जब यूरिया खाद के टोकन लेने को लेकर किसानों के बीच जमकर मारपीट हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खाद के लिए सुबह से ही सैकड़ों किसान लाइन में लगे हुए थे. जैसे ही कुछ ग्रामीण बिना क्रम तोड़े लाइन में घुसकर टोकन लेने लगे, विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लात-घूंसे चलने लगे. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी. पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और किसानों को शांत कराया.

जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही सरकार, विपक्ष का वाकउट

स्टांप संशोधन विधेयक का विपक्ष ने जताया विरोध

सदन में 4 विधेयकों पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. सदन में बुधवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विभाग से संबंधित चार विधेयकों पर एक साथ चर्चा हुई. चारों विधेयकों को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

इस बीच विपक्ष ने मप्र स्टॉम्प मप्र द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 का जमकर विरोध किया और इसे जनविरोधी करार देते हुए वापस लेने की मांग की. जब उनकी मांग अनसुनी कर दी गई तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए वाकआउट कर दिया. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित चार विधेयक क्रमश: भारतीय स्टाम्प मप्र संशोधन विधेयक 2025, मप्र माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, रजिस्ट्रीकरण मप्र संशोधन विधेयक 2025 और भारतीय स्टॉम्प मप्र द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक साथ चर्चा कराने की व्यवस्था दी. इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने माल एवं सेवा कर के बारे में कहा कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को मूर्तरूप देने और टैक्स के मामले में पूरे देश में एकरूपता लाने के लिये विधेयक को प्रदेश में भी पारित कराना जरुरी है. उन्होंने कहा कि इससे आम कर दाताओं को राहत मिलेगी और प्रदेश में टैक्स में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि नये संशोधन से व्यवसायियों को ज्यादा टैक्स क्रेडिट मिलेगा.

> इसके पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदन को विधेयक बनाने का अधिकार है, लेकिन इसका उद्देश्य आम जनता के हितों की रक्षा होना चाहिए, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने स्टांप ड्यूटी भरने वालों से कोई राय ली? एक तरफ कहा जाता है कि टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ शुल्कों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि सरकार कर्ज लेकर विकास कर रही है, तो जनता पर अतिरिक्त शुल्क थोपने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई का हवाला देकर शुल्क बढ़ा रही है, जबकि खुद हर ज़रूरी चीज़ पर जीएसटी वसूल रही है. उमंग सिंघार ने विशेष रूप से अचल संपत्ति के एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क की वृद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले यह शुल्क 1000 रुपये था, अब इसे 5000 कर दिया गया है.

पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर अनोखा प्रदर्शन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. विधानसभा परिसर में बुधवार को गांधी प्रतिमा के सामने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस विधायक दल ने प्रदर्शन किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में सभी कांग्रेस विधायक पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की साथ ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया. बाद में पत्रकारों से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाए गए. जांच में सामने आया है कि फिंगरप्रिंट, फोटो, हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग तक मेल नहीं खा रहे. फर्जी आधार कार्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया.

अब घर पहुंचेगा ड्राइविंग लायसेंस

चर्चा का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री ने किया आश्वस्त

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. प्रदेश में अब ड्राइविंग लायसेंस पासपोर्ट की तरह घर पहुंचेगा. ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये फेसलेस प्रक्रिया भी शुरू होगी. परिवहन विभाग संपर्क विहीन व्यवस्था बनाने की तैयारी में है, जिससे कि परिवहन विभाग से जुड़े कामों के लिये विभाग के अमले से संपर्क ही न करना पड़े.

अपने मोबाइल से ही लर्निंग लायसेंस बनाया जा सकेगा, टैक्स, पैनाल्टी सहित अन्य शुल्क भी व्यक्ति घर बैठे ही जमा कर सकेगा. यह जानकारी बुधवार को सदन में परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह ने मप्र मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दी. मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही नये अधिनियम की जरुरत महसूस हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले मोटरयान का टैक्स जमा नहीं करने पर देय कर पर महज 4 फीसदी की दर से पैनाल्टी की गणना की जाती थी, जो कि लंबित देयक से दोगुना से अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है. अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों द्वारा देय कर जमा नहीं करने पर उनके देय कर की चार गुना तक पैनाल्टी अब लगाई जायेगी.

> **चेक पोस्ट बंद होने के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुका**
>
> इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश में परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. कांग्रेस के विजय रेवनाथ चौरे ने कहा कि चेक पोस्ट बंद कर दिये, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका. सौरभ शर्मा तो छोटी मछली है. उसके पास 52 किलो सोना और करोड़ों की नगदी कहां से आ गई. इसके पीछे कौन है.

प्रदेश में कब तक असुरक्षित रहेंगी बेटियां : जीतू

सीधी में दलित युवती से गैंगरेप, जंगल में पांच दरिंदों ने किया हमला

भोपाल/सीधी, 06 अगस्त. सीधी जिले से एक बार फिर मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. चुरहट के जंगल में एक दलित युवती के साथ पांच बदमाशों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

इस शर्मनाक वारदात ने प्रदेश में महिलाओं, विशेषकर दलित और आदिवासी वर्ग की बेटियों की सुरक्षा पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने ट्वीट पर कहा, मुख्यमंत्री बनाम गृहमंत्री, अब सीधी में एक दलित युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. 5 बदमाशों ने चुरहट के जंगल में यह शर्मनाक कृत्य किया है. सिस्टम की पोल खोलती इस घटना से मप्र की लाड़लियों के मन में असुरक्षा पैदा हो रही है. पटवारी ने भाजपा सरकार से सवाल किया है कि आखिर कब तक प्रदेश की बेटियां असुरक्षित रहेंगी और पुलिस-प्रशासन कब नींद से जागेगा? बीते 3 वर्षों में प्रदेश में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की 7,418 घटनाएं, 558 हत्याएं और 338 गैंगरेप के मामले दर्ज हुए हैं. औसतन हर दिन 7 दलित, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है. उन्होंने देवास, भिंड, नरसिंहपुर और अन्य जिलों की घटनाओं पर कहा कि कभी जिंदा जलाया जाता है, तो कभी एफआईआर नहीं होती है.

> **नशा अब ठेले पर मिलने लगा है : कांग्रेस**
>
> नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक बार फिर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने ट्विटर पर सवाल उठाते हुए लिखा, गृहमंत्री, नशा अब ठेले पर मिलने लगा है! इसका ठेका किसे मिला है? नेता प्रतिपक्ष सहित कई कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मप्र में नशे का कारोबार संगठित तरीके से फल-फूल रहा है और युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला गरमाया

आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे जांच, विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा

भोपाल, 06 अगस्त . सतना जिले के अमरपाटन में करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और राजस्व अभिलेखों में जमीन को दर्ज नहीं करने के मामले में अब आयुक्त स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाएगी. यह घोषणा सोमवार को विधानसभा में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने की.

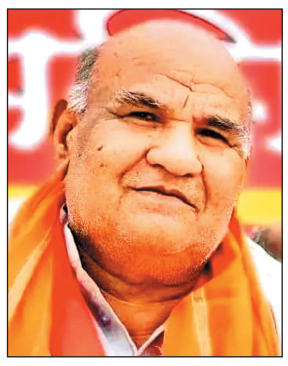

अमरपाटन के विधायक राजेंद्र सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला सदन में उठाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम उमराही मथुरियान की बेशकीमती भूमि को वर्ष 2003 में शासकीय भूमि घोषित किए जाने के आदेश तहसीलदार द्वारा दिए गए थे.

इस आदेश को वर्ष 2022 में रीवा के तत्कालीन संभागायुक्त ने भी यथावत माना, बावजूद इसके अब तक जमीन को राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज नहीं किया गया है. अब इस प्रकरण पर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच कब शुरू होगी और किन-किन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

> **भूमाफिया की मिलीभगत का आरोप**
>
> विधायक सिंह ने सदन में आरोप लगाया कि इस मामले में तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है, जिसने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर जमीन पर अवैध कब्जा करवा दिया. उन्होंने इस भूमि की कीमत करोड़ों रुपए बताई और इसे राज्य की संपत्ति के साथ धोखा करार दिया. जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने माना कि इस मामले में गंभीर गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे हैं और सरकार इसे हल्के में नहीं लेगी. उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि आयुक्त स्तर के अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मृत घोषित कर निकाले 6 लाख रुपए

अशरफ और शौकत जिंदा हैं, पर सिस्टम ने मरा बता दिया!

धार,06 अगस्त. हम जिंदा हैं साहब, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में मर चुके हैं! धार जिले के नालछा जनपद पंचायत के मगजपुरा गांव में रहने वाले अशरफ पटेल और शौकत पटेल इन दिनों इसी गूंज के साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.

वर्ष 2022 में इन्हें कागजों पर मृत घोषित कर मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत भवन कर्मकार योजना और अंत्येष्टि सहायता योजना से करीब 6 लाख रुपये निकाल लिए गए. पीड़ित अशरफ और शौकत ने बताया कि वे उस समय भी गांव में जीवित और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे. बावजूद इसके, योजना की पूरी राशि किसी और ने निकाल ली और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी. अशरफ ने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर मिलीभगत से उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस ठगी को अंजाम दिया गया.

यह मामला सरकारी योजनाओं में गहराए भ्रष्टाचार को उजागर करता है. बल्कि यह भी दिखाता है कि आम जनता को आज भी अपने जिंदा होने का प्रमाण सरकारी फाइलों में देना पड़ रहा है. सवाल यह है कि अगर नागरिक को अपने अस्तित्व को ही बार-बार साबित करना पड़े, तो ऐसे सिस्टम से भरोसा कैसे किया जाए?

> **न्याय के लिए दौड़, प्रशासन मौन**
>
> दोनों पीड़ित पहले नालछा थाने में शिकायत कर चुके हैं, फिर जनपद पंचायत सीईओ संदीप डाबर को आवेदन सौंपा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अंतत: दोनों ने धार जिला मुख्यालय में जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार के सामने अपनी व्यथा रखी. अपर कलेक्टर ने माना कि कहीं न कहीं सिस्टम में बड़ी चूक हुई है और इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जवान ने बैरक में की आत्महत्या

शराब की लत ने ले ली जान!

मुरैना,06 अगस्त. शराब की लत और मानसिक तनाव में डूबे एसएएफ के एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली. घटना बुधवार को मुरैना में स्थित पांचवीं बटालियन की है, जहां आरक्षक रवींद्र शर्मा ने बैरक में ही कपड़े सुखाने के तार से गमछा बांधकर फांसी लगा ली.

घटना के समय बैरक में कोई मौजूद नहीं था. रवींद्र शर्मा ग्वालियर जिले के डबरा तहसील के बरैड़ा गांव का निवासी था और वर्ष 2003 में एसएएफ में भर्ती हुआ था. जानकारी के मुताबिक, रवींद्र शराब का आदी था और मानसिक तनाव में जी रहा था. इससे पहले भी वह दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था.

कमांडेंट बोले-समझाने के बाद भी नहीं मानी बात

एसएएफ कमांडेंट रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि रवींद्र को कई बार शराब छोड़ने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसने नहीं सुना. अक्सर वह ड्यूटी से भी गायब रहता था. डिप्टी कमांडेंट कमल मौर्या के अनुसार, रवींद्र अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन में रहता था और शराब की लत के कारण परिवार से भी दूर हो गया था. मुरैना एसपी समीर सौरभ ने बताया कि रवींद्र को एक माह पहले ही पांचवीं बटालियन में पोस्ट किया गया था.

कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल

197 मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं

'लव जिहाद' और पुलिस पर हमले : विधानसभा में खुलासा

भोपाल,06 अगस्त. मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को सरकार ने राज्य में महिला अपराध, धर्मांतरण मामलों और पुलिस पर हमलों के ताज़ा आंकड़े सदन में पेश किए. आंकड़े चौंकाने वाले हैं और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

जनवरी से जून 2025 तक प्रदेश में 3,742 महिलाओं के साथ बलात्कार, और 120 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज हुईं. इन मामलों में सिर्फ 2.79 प्रतिशत में दोष सिद्धि हुई, जबकि गैंगरेप में सजा का प्रतिशत मात्र 1.63 प्रतिशत रहा. विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर यह जानकारी दी गई. 2018 से 2024 के बीच कुल 54,067 बलात्कार हुए. इनमें अनुसूचित जाति की 14,258, जनजाति की 14,804, पिछड़ा वर्ग की 18,942 और सामान्य वर्ग की 6,063 महिलाएं पीड़िता थीं. वर्ष 2018 में बलात्कार के 7,136 मामलों की तुलना में 2024 में 8,518 मामले दर्ज हुए यानी 20 प्रतिशत वृद्धि. वहीं अपहरण के मामलों में 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 6,394 से बढ़कर 10,070 हो गए.

> **'लव जिहाद' के 283 मामलों में सिर्फ 7 सजा**
>
> विधायक आशीष गोविंद शर्मा के प्रश्न के उत्तर में गृह विभाग ने बताया कि 2020 से अब तक 'धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' के तहत 283 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से 197 मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं. अब तक 87 मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें 50 मामलों में आरोपी बरी, सिर्फ 7 मामलों में सजा हुई. एक केस में दोनों पक्षों में समझौता हुआ. सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि कई मामलों में पीड़िता की गवाही कमजोर होने के चलते आरोपी छूट गए. इन मामलों में सबसे ज्यादा केस इंदौर (74), भोपाल (31), खरगोन (13), धार (13), और छतरपुर (11) जिलों से दर्ज हुए हैं.

इंदौर से गोवा के लिए इंडिगो की तीसरी उड़ान 26 अक्टूबर से

इंदौर,06 अगस्त. इंदौर से गोवा की हवाई यात्रा और भी सुगम होने जा रही है. इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर से इंदौर-गोवा के बीच तीसरी सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है.

कंपनी ने इस नई फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू कर दी है. वर्तमान में इंदौर से गोवा के लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक-एक उड़ान संचालित हो रही है. पर्यटन सीजन को देखते हुए इस नई उड़ान की मांग काफी समय से की जा रही थी. अक्टूबर से फरवरी के बीच इंदौर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में पर्यटक गोवा की ओर रुख करते हैं. ट्रेन और बस से दो दिन लगने के कारण अधिकांश यात्री विमान से जाना पसंद करते हैं.

ट्रैवल एजेंट्स ऑफ इंडिया मध्यप्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार, नई उड़ान का समय सुबह 8:55 बजे निर्धारित किया गया है. फ्लाइट 10:35 बजे गोवा पहुंचेगी, जिससे पर्यटक होटल में चेक-इन कर उसी दिन गोवा घूमने की योजना बना सकेंगे.

बैठक सीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की

फ्लैगशिप योजनाओं के साथ निवेश की देंगे जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार मुख्य अतिथि अपने संबोधन में जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, जिले में आए निवेश, कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में हुए विकास और अन्य उल्लेखनीय गतिविधियों के बारे में भी नागरिकों को जानकारी देंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. जिसमें मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिये हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है. यह अवसर हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और योगदान को स्मरण करने तथा उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.

बैठक में तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का सभी जिलों में होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाईव प्रसारण किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पूरे हर्ष उल्लास, गरिमा और जन सहभागिता के साथ हो. विशेष रूप से युवा वर्ग में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाये. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यस्तरीय समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की.

> समारोह में लोकतंत्र सेनानियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होकर देशभक्ति के संदेश का प्रसार करें. बैठक में मंत्रीगण द्वारा राज्य एवं जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में गरिमा के अनुरूप नवाचारों के संबंध में सुझाव भी दिए गए. अधिकारियों द्वारा समारोह के सुचारु आयोजन के लिए की जा रही व्यापक तैयारियों की सिलसिलेवार जानकारी दी गई.

परिचालन में शत-प्रतिशत तत्परता रखें

रेल प्रबंधक त्यागी का आरकेएमपी से खंडवा रेलखंड का दौरा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 06 अगस्त. पमरे भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने बुधवार को रेलखंड का निरीक्षण किया. रानी कमलापति से खंडवा रेलखंड का प्रथम विंडो ट्रेलिंग का इस दौरान उन्होंने जायजा लिया.

निरीक्षण का उद्देश्य खंड में चल रहे अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा करना, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेना तथा संरक्षा मानकों का परीक्षण करना था. त्यागी ने निरीक्षण के समापन पर सभी विभागों को निर्देश दिए कि मॉनसून सीजन को दृष्टिगत रखते हुए संरक्षा एवं परिचालन में शत-प्रतिशत तत्परता बनाए रखें, तथा यात्रियों को उत्तम सुविधा देने हेतु सभी योजनाओं को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जाए. इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर विभिन्न संरक्षा, परिचालन एवं यात्री सुविधा से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया. अपर मंडल रेल प्रबंधक अभिराम खरे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) ऋतुराज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे.